



एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश कितनी दूर तक जाता है! इसी तरह इस बुरी दुनिया में एक अच्छा काम चमचमाता

मूल्य
₹ 3/-

-विलियम शेक्सपीयर

जिद...सत्त की

सांघ्य दैनिक

4 PM

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork [@Editor_Sanjay](https://twitter.com/Editor_Sanjay) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/@4pm NEWS NETWORK)

• तर्फः 8 • अंकः 47 • पृष्ठः 8 • लखनऊ, सोमवार, 21 मार्च, 2022

मार्च में ही आसमान से बरसने... 7 नई विधान सभा में हर चौथा विधायक... 3 भाजपा के संरक्षण में अपराधी... 2

योगी की ताजपोशी को भव्य बनाने की तैयारी, दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा

- » 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद
- » विपक्षी दलों के नेताओं को भी भेजा गया न्योता, शाह 23 को पहुंचेंगे लखनऊ
- » विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम का होगा औपचारिक ऐलान □□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी भाजपा अब नयी सरकार के गठन में जुट गयी है। वहीं योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी का समारोह भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। इकाना स्टेडियम को सजाया जा रहा है। यहीं पर योगी



आदित्यनाथ दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी

कराया जाएगा मुंह मीठ

समारोह में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए गिरीष सहित पानी की व्यवस्था की जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार को इस पूरे काम का जिम्मा सौंपा गया है। इसने एफएसई और आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी लागाया गया है। करीब 100 अधिकारियों के हवाले पूरी व्यवस्था देगी।

नड़ा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। विपक्षी दलों के देश भर के प्रमुख नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा गया है।

योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ

ग्रहण समारोह के लिए करीब 50 हजार अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वे 23 मार्च को लखनऊ

दिखेगा बदले मत्रिमंडल का स्वरूप

मत्रिमंडल ने जातीय समीकरणों के साथ विधायकों की उच्च शिक्षा और उनके प्रोफेशनल और प्रशासनिक अनुबंध पर फोकस किया जाएगा। इस बार मात्रा गतिविधि से 32 महिलाएं जीतकार आई हैं। उन्हें नीं मत्रिमंडल में जगह मिलेगी। भाजपा को गैर व्यावर पिछड़े के अलावा दिलीते और महिलाओं का गृह बहावत में मिल गया। बस्ता के विसर्के दलित गैर बैंक ने मात्रा जो चुना है। इसके बाद गैर दिलीतों की मत्रिमंडल में विस्तैदारी बढ़ेगी।

फूलों से सजाया जा रहा पूरा इलाका

इकाना स्टेडियम और आसपास का इलाका फूलों से सजाया जा रहा है। लखनऊ डेल्पोर्नेट अथेटिटी (एलडीए) ने 112 मुख्यालय से लेकर शैया ग्रहण स्थल इकाना स्टेडियम तक की पूरी सड़क को फूलों से सजा दिया है। इसके लिए ऐसे लाठे टार्ट करीब पाँच हजार से ज्यादा छोड़ दें गए लोगों में फूलों के पांच सजाए गए हैं। शहीद पथ की सजाया जा रहा है।

पहुंचेंगे। वे 24 को विधायकों से मुलाकात करेंगे। शाह विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के तौर योगी आदित्यनाथ का औपचारिक चयन होगा। इसके बाद योगी 25 मार्च को अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे। वहीं सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं।

गरीबी व कुपोषण को लेकर अखिलेश ने भाजपा को घेरा, कहा ये तमगे हैं सरकार की नाकामी के

- » सपा प्रमुख ने नीति आयोग की रिपोर्ट का दिया हवाला देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल यूपी
- » प्रदेश में बढ़ते बाल मृत्यु दर का भी उठाया मुद्दा □□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार के विकास के दावों को लेकर जमकर हमला बोला है। प्रदेश में गरीबी, कुपोषण और बाल मृत्यु दर को लेकर आयी नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज करते हुए कहा है कि ये भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने टिवटर हैंडल से एक खबर भी पोस्ट की है, जिसमें नीति आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने

कुपोषण में यूपी का हाल बेहाल

बिहार में कुपोषण के विकार लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद झारखण्ड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर है। मानवता स्वास्थ्य से विवित आबादी, स्कूल नहीं जाने, एसेंड ईंजन और बिल्ली से विवित लोगों के मामले में भी बिहार की विवित सभासे खराब है। बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सभासे खराब है। इस मामले में इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। खल्काल से विवित आबादी के मामले में झारखण्ड की ईकिंग सभासे खराब है।

टिवटर हैंडल पर लिखा, भाजपा के राज में नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में उपर देश के सबसे गरीबी तीन राज्यों में शामिल है, सबसे अधिक कुपोषण में उपर तीसरे स्थान पर है तथा बाल व किशोर मृत्यु दर श्रेणी में पूरे देश में उपर सभासे खराब स्थिति में है। ये भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे हैं। गैरतलब है कि नीति आयोग ने अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक

संगठन का विस्तार करने में जुटी आप कई राज्यों के प्रभारियों का ऐलान

- » केजरीवाल ने अपने सिपहसालार संदीप को गुजरात में उतारा
- » सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी
- » 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब बाकी राज्यों में पैर पसाराने की तैयारी में है। इसके लिए कई राज्यों में आप ने संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया है। गुजरात की जिम्मेदारी संदीप पाठक को दी गई है। पंजाब विधान सभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने शनिवार जीत दर्ज करके सरकार बनाई। इस जीत का श्रेय संदीप पाठक को दिया जा रहा है।

आप ने छत्तीसगढ़ में दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय को प्रभारी बनाया है। संतोष श्रीवास्तव को संगठन मंत्री बनाया गया। पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को हरियाणा में चुनाव प्रभारी बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मनीष सिसोदिया के करीबी रहे रत्नेश गुरु पहले ही हिमाचल प्रभारी बनाया गया है।



राज्य सभा के उम्मीदवार घोषित

पंजाब से राज्य सभा के लिए आम आदमी पार्टी ने आपों नामों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों के लिए क्रिकेटर रघुवर दिल्ली, पंजाब के प्रोफेशनल संदीप पाठक के नाम घोषित किया गया है। आप ने लवली ग्रूपिंग ब्रेस्ट कैंसर के चालाल असेक मिलाल और कृष्ण प्राण ब्रेस्ट कैंसर के नाम का भी ऐलान किया है। सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर दिया है।

में पार्टी का प्रभार संभाल रहे हैं। गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश में इस साल विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने वहीं भी चुनाव प्रभारी बनाया है। केरल में एराजा को प्रभारी बनाया गया है। विनय मिश्रा को पार्टी ने राजस्थान की कमान सौंपी है तो मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को तेलंगाना का चुनाव प्रभारी बनाया गया है।



नई विधान सभा में हर चौथा विधायक ठाकुर या ब्राह्मण, यादव से ज्यादा कुर्मी प्रत्याशी पहुंचे सदन

» इस बार विधान सभा में मुस्लिम विधायक भी बढ़े

» जाति आधार पर टिकट बंटवारे का फॉर्मला हिट

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने-अपने हिसाब से सियासी समीकरण को साधने का दाव चला था। जाति आधार पर टिकट बंटवारे किए गए थे। बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मला योगी आदित्यनाथ के लिए हिट रहा तो सर्वांग समुदाय के लिए सुपरहिट रहा है। यूपी चुनाव नीतीजे से योगी सरकार के सत्ता में वापसी के साथ-साथ ब्राह्मण समुदाय से सबसे ज्यादा विधायक जीतकर आए हैं तो दूसरे नंबर पर ठाकुर विधायकों की संख्या है।

वहाँ, पिछली बार से ज्यादा मुस्लिम विधायक इस बार जीतकर आए हैं। यूपी की सियासत में ब्राह्मणों का दबदबा पूरी तरह से कायम है। इस बार 403 सीटों में से 52 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 46 बीजेपी से हैं जबकि पांच सपा और एक कांग्रेस से जीत दर्ज की है। ऐसे ही 49 विधायक ठाकुर समाज से जीतकर आए हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन से 43, सपा से 4, बसपा से एक और जनसत्ता पार्टी से राजा भैया हैं। इस तरह से सूबे में हर आठवां विधायक ब्राह्मण है जबकि चौथा विधायक ठाकुर या ब्राह्मण है।



दलितों में जाटव विधायकों का दबदबा

उत्तर प्रदेश में दलितों में इस बार बीजेपी ने फिर बाजी मारी है और खासकर जाटव समुदाय के बीच। सबसे ज्यादा बीजेपी से जाटव समुदाय के विधायक जीते हैं, जिनकी संख्या 19 है जबकि 10 सपा गठबंधन से। बसपा ने सबसे ज्यादा जाटवों का वोट पाया लेकिन उनका एक विधायक नहीं जीत सका। दलित में जाटवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी पासी है। बीजेपी से 18 पासी विधायक बने हैं तो सपा से 8 और एक जनसत्ता पार्टी से जीत दर्ज की है।

कायरथ समाज की भी तीन सीटें

कायरथ समाज ने 3 सीटें जीती हैं। सभी बीजेपी से जीते हैं। दलित गाल्मीकि से एक वह सीट बीजेपी को मिली है जबकि एक सिख जीता है वह भी बीजेपी के टिकट पर विधान सभा पहुंचे हैं।

यादव से ज्यादा कुर्मी विधायक बनने में सफल

यूपी में ओबीसी समुदाय में इस बार सबसे ज्यादा कुर्मी समुदाय से विधायक चुने गए हैं जबकि ओबीसी में उनकी आबादी यादव समुदाय से कम है। सूबे में 41 कुर्मी विधायक जीते हैं, जिनमें 27 बीजेपी गठबंधन से, 13 सपा गठबंधन से और एक कांग्रेस पार्टी से जीतकर सदन पहुंचे। वहाँ, इस बार यादव विधायक की कुल संख्या सदन में 27 है, जिसमें से 24 सपा और तीन बीजेपी से जीत कर आए हैं।

बढ़ गया मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व

सूबे में भले ही सपा गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही हो लेकिन मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ गया। इस बार मुस्लिम विधायकों की संख्या 34 पर पहुंच गई है, जिसमें 32 सपा से और दो आरएलडी से जीते हैं। वहाँ, 2017 के चुनाव में 23 मुस्लिम विधायक ही जीतकर आए थे जबकि इस बार बढ़कर 34 विधायक हो गए हैं। हालांकि, मुस्लिमों की आबादी के लिहाज से ये संख्या कम है।

राजभर समाज पर सपा गठबंधन का कछा

गुर्जर बिरादरी से कुल 7 विधायक जीते हैं, जिनमें पांच बीजेपी से और दो सपा से जीते हैं। राजभर बिरादरी में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बाजी मारी है। सपा गठबंधन से तीन राजभर समुदाय के विधायक जीत कर आए हैं जबकि बीजेपी से एक विधायक को जीत मिली। भूमिहार बिरादरी के 5 विधायक बने हैं, जिसमें से चार बीजेपी और एक सपा गठबंधन से है। दलितों की धोबी बिरादरी से सभी 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं जबकि खटीक समाज से 5 जीते हैं, जिसमें से 4 बीजेपी से और एक सपा गठबंधन से हैं।

जाट समुदाय के 15 विधायक जीते

पश्चिमी यूपी में सियासी तौर पर दबदबा रखने वाली जाट समुदाय एक बार फिर बड़ी तादाद में जीत कर आए हैं। सपा और बीजेपी लाभग्रह बराबर जाट समुदाय ने जीत दर्ज की है। इस बार कुल 15 जाट चुनकर आए हैं, जिसमें 8 बीजेपी से और 7 सपा गठबंधन से विधायक बने हैं।

तैरथ समुदाय का मात्र एक विधायक सपा से

बनिया और खत्ती बिरादरी में बीजेपी का फिर जलवा रहा। इन दोनों समुदाय के 22 में से 21 बीजेपी से जीते हैं जबकि एक सपा से जीत दर्ज की है। पिछड़ी जाति में लोध एक बार फिर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। लोध समुदाय से कुल 18 लोग जीतकर सदन पहुंचे हैं, जिसमें से 15 बीजेपी से जबकि तीन सपा से जीते हैं।

गैर-यादव ओबीसी में बीजेपी का वर्चस्व

गैर यादव ओबीसी में बीजेपी ने फिर बाजी लाई है। नौर्य, कुर्माल, शायव और बैनी में बीजेपी ने 12 सीटें जीती हैं जबकि सपा गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली है। अति पिछड़ी जातियों में बीजेपी 7 और सपा को तीन सीटें मिली। निषाद, दिव कर्याप मलाह इन जातियों में भी सबसे ज्यादा 6 विधायक बीजेपी गठबंधन से सदन में पहुंचे हैं जबकि सपा से दो विधायक जीते हैं। कलवार, तेली, सोनार जातियों से भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें जीती जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली।

यूपी के तीन सबसे गरीब विधायक

खुद का घर नहीं, थोड़े से रूपए लेकर चुनाव लड़े और जीत भी गए | यूपी में 91 फीसदी विधायक करोड़पति



□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। यूपी विधानसभा में इस बार कई तरह की विविधताएं दिखाई देंगी। पहली बार रिकॉर्ड 47 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। दूसरी ओर 91 फीसदी ऐसे प्रत्याशी चुनकर विधान सभा पहुंचे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। हालांकि कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो काफी गरीब हैं। इनके पास खुद का घर भी नहीं है। 403 में से 366 विधायक ऐसे चुने गए, जिनके पास एक करोड़ या इससे ज्यादा की संपत्ति है। इस बार यूपी में गरीबों की आवाज उठाने के लिए 91 फीसदी करोड़पति विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। मतलब 403 में से 366 विधायक करोड़पति हैं।

इनके पास एक करोड़ या इससे अधिक की दौलत है। विधायकों की औसतन संपत्ति 8.06 करोड़ रुपये है। 2017 में चुने गए 80 फीसदी विधायक करोड़पति थे। मतलब इस बार इसमें दस फीसदी का इजाफा हुआ है। खैर, इन सबके बीच कुछ ऐसे नाम भी सामने

चुनकर जाने वाले सबसे गरीब विधायक हैं। वहाँ कई विधायक ऐसे भी हैं, जो कर्ज में डूबे हैं या यूं कहें उन पर लेनदेन या कर्जा है।

अनिल प्रधान (सपा)

पित्रकृष्ण से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे अनिल प्रधान यूपी के सबसे गरीब विधायक है। इनके पास महज 30 हजार 40 रुपये की संपत्ति है। अनिल के नाम खुद का न तो कोई घर है और न ही कोई जनीन। अनिल ने अपने हलफनारों में इसकी जानकारी दी है।

श्रवण कुमार निषाद (भाजपा)

गोरखपुर के योगी-यौवा सीट से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यार्थी श्रवण कुमार निषाद यूपी के दूसरे सबसे गरीब विधायक है। श्रवण के पास कुल 72 हजार 996 रुपये की संपत्ति है। श्रवण ने बताया कि उनके नाम न तो कोई मकान है और न ही कोई जनीन है।

गुडिया कठेरिया (भाजपा)

ओडिया सीट से विधायक गुडिया कठेरिया तीसरी सबसे गरीब विधायक है। गुडिया के पास कुल 10.75 लाख रुपये की संपत्ति है। हालांकि गुडिया के नाम न तो कोई मकान है और न ही कोई जनीन।

राकेश पांडेय (सपा)

आए, जिन्होंने चुनाव में प्रत्याशियों के साथ धनबल और बाहुबल को भी हराया।

हम आपको ऐसे ही तीन नामों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये यूपी विधानसभा में

अबेंकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक चुने गए। ओमप एवं कुल 2 करोड़ रुपये की देनदारी है। अबर उनके संपत्ति के बारे में बत करें तो उनके पास कुल 34 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

राकेश सचान (भाजपा)

कानपुर देहत के भोगनीपुर से भाजपा के राकेश सचान विधायक अमित अग्रवाल कर्जदार विधायकों की सूची में दूसरे नंबर पर है। अमित पर कुल 13 करोड़ रुपये का कर्ज है। वहाँ, ओरगांडल संपत्ति देखें तो इनके पास कुल 148 करोड़ रुपये की ज्यादा है।

उमारांकर सिंह (बसपा)

बलिया के इक्का सीट से उमारांकर सिंह ने चुनाव जीता है। उमारांकर विधायक के इक्का सीट से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

विकास गुप्ता (भाजपा)

फलाइपुर की योगी-यौवा सीट से जीतने वाले गुप्ता के विकास गुप्ता की संपत्ति है, लेकिन वह 12 करोड़ रुपये की कर्ज में भी डूबे हैं।

ओम कुमार (भाजपा)

बांदा से भाजपा के प्रकाश दिवेरी विधायक चुने गए हैं।

प्रकाश दिवेरी के मटोना सीट से समाजवादी पार्टी की मारिया ने चुनाव जीता है।

मारिया के अपने चुनावी हालफनारों में बताया है कि उनके पास कुल 27 करोड़ रुपये की संपत्ति है।



Sanjay Sharma

f editor.sanjaysharma

t @Editor_Sanjay

“

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना के 1.10 करोड़ से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं जो इससे पहले के हफ्ते से 8 फीसदी ज्यादा हैं। चीन और दक्षिण कोरिया में कोरोना के मामले 25 फीसदी और मौतें 27 फीसदी तक बढ़ गई हैं। अफ्रीका में भी नए मामलों में 12 फीसदी और मौतों में 14 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि यूरोप में नए मामलों में 14 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि यूरोप में मौतों का अंकड़ा स्थिर बना हुआ है। इसके कारण दुनिया भर के विशेषज्ञ अब एक और लहर वैश्विक अर्थिक मंदी को न्योता नहीं देगी? क्या कोरोना प्रोटोकॉल में लापरवाही के कारण हालात बिगड़ रहे हैं? क्या भारत की स्वास्थ्य सेवाएं एक और लहर को संभाल सकतीं?

जिद... सच की

कोरोना की रफ्तार ने फिर बढ़ाई चिंता

दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक एक सप्ताह में संक्रमण दर में आठ फीसदी का उछाल आया है। चीन समेत कई यूरोपीय देशों में इसका प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना के ताजा हालातों को देखते हुए भारत में चौथी लहर की आशंका जतायी जाने लगी है। लिहाजा सरकार ने एक बार फिर राज्यों को अलर्ट किया है। सबाल यह है कि वैश्वीनेशन के बावजूद कोरोना वायरस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्या एक बार फिर दुनिया भर में पारबंदियों का दौर शुरू हो सकता है? क्या भारत ने इसको रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति बनायी है? क्या एक और लहर वैश्विक अर्थिक मंदी को न्योता नहीं देगी? क्या कोरोना प्रोटोकॉल में लापरवाही के कारण हालात बिगड़ रहे हैं? क्या भारत की स्वास्थ्य सेवाएं एक और लहर को संभाल सकतीं?

देश में कोरोना संक्रमण भले काबू में आता दिख रहा हो लेकिन पड़ोसी मुलक चीन समेत कई देशों में बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन समेत सर्विलास और जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। चीन की हालत सबसे खराब है। यहां रोजाना तीन हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां ओमिक्रॉन का सब-वैरिएंट बीए-2 तबाही मचा रहा है। वहाँ कुछ देशों में डेल्टाक्रॉन वैरिएंट के केस सामने आ रहे हैं। हांगकांग, दक्षिण कोरिया समेत अफ्रीकी और यूरोपीय देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना के 1.10 करोड़ से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं जो इससे पहले के हफ्ते से 8 फीसदी ज्यादा हैं। चीन और दक्षिण कोरिया में कोरोना के मामले 25 फीसदी और मौतें 27 फीसदी तक बढ़ गई हैं। अफ्रीका में भी नए मामलों में 12 फीसदी और मौतों में 14 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि यूरोप में नए मामले दो फीसदी बढ़े हैं। हालांकि, यूरोप में मौतों का अंकड़ा स्थिर बना हुआ है। इसके कारण दुनिया भर के विशेषज्ञ अब एक और लहर की आशंका जताने लगे हैं। वैश्वीनेशन के बावजूद इन देशों में कोरोना के केस बढ़ने से भारत में भी चिंता बढ़ गयी है। यदि एक और लहर आयी तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को कोरोना के मददेनजर तैयार करना होगा। वहाँ आम आदमी को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। वैश्वीनेशन और प्रिकाशन डोज की रफ्तार भी बढ़ानी होगी और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर नजर रखनी होगी। अन्यथा हालात फिर खराब हो सकते हैं।

—
१४८

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

गोपाल कृष्ण

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती करने का गलियारा बनाया जायेगा। उसके बाद अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि देश की 13 बड़ी नदियों—झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और गोदावरी—के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने एवं उसका संरक्षण करने, भूजल का स्तर और बन उत्पादन बढ़ाने की मंशा से की गयी यह पहल सराहनीय है। इस योजना के तहत 19 हजार करोड़ रुपये की लागत से 74 सौ वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बन उत्पादन होगा पर इसमें एक यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या वृक्षारोपण को बन लगाने की त्रेणी में रखा जा सकता है।

दूसरी बात नदियों के बाढ़ मैदानों से जुड़ी हुई है। हर नदी के बाढ़ क्षेत्र की मिट्टी के स्वभाव और उसकी परिस्थितिकी का समुचित अध्ययन कर अनुकूल पेड़-पौधे लगाने होंगे। ये क्षेत्र नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। अलग-अलग मौसम में इन्हीं क्षेत्रों में नदी अपने को बढ़ाती हैं या पुनर्जीवित करती हैं। ऐसा न हो कि इस योजना के तहत उसमें कोई अतिक्रमण हो इसलिए परियोजना के अध्ययन रिपोर्ट के बाद पर्यावरण संबंधी लेखा-जोखा भी होना चाहिए ताकि सही मंशा के बावजूद किसी तरह की गलती या गड़बड़ी को रोका जा सके और प्राकृतिक संवेदनशीलता का संरक्षण हो सके। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की विभिन्न नदियों पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। अब तक

नदी संरक्षण के लिए उचित पहल

की योजनाओं में आम तौर पर गंगा नदी को प्राथमिकता मिलती रही है। लगभग सभी नदी घाटियों में समस्याएं हैं। नदी बेसिन में पानी की कमी हो रही है। आसपास का पर्यावरण खतरे में है। इस लिहाजे से पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालयों की संयुक्त पहल स्वागतयोग्य है।

छोटी-छोटी नदियों को भी हमें प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि वे ही एक तरह से बड़ी नदियों का आधार होती हैं। इन सभी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र नसों और धर्मनियों की तरह आपस में जुड़े होते हैं। उल्लेखनीय है कि इन 13 नदियों के संवर्धन और संरक्षण की प्रक्रिया से उनसे संबंधित दो सौ से अधिक छोटी नदियों का भला हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता बेहतर हुई है। संभव है कि सांचियक रूप से आंशिक प्रदूषण का भी संज्ञान लेखा-जोखा भी होना चाहिए। नदियों को बचाने और उनकी बेहतरी के प्रयास में हमें रासायनिक खेती तथा उद्योगों से होनेवाले प्रदूषण का भी संज्ञान लेखा चाहिए। जब तक औद्योगिक व रासायनिक खेती



होती रहेगी और उद्योगों का कचरा नदियों में प्रवाहित होता रहेगा। पानी के साथ-साथ मिट्टी और पेड़-पौधों को भी नुकसान होता रहेगा। बीते अनेक वर्षों से पर्यावरण की स्थिति से संबंधित रिपोर्टों में रेखांकित किया जाता रहा है कि हमारे देश में 45 प्रतिशत के आसपास क्षेत्र भू-क्षरण की समस्या से ग्रस्त है। जिन 13 नदियों के किनारे बन उत्पादन होनी चाहिए। इन नदियों के तहत जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव है उनके दायरे में देश की लगभग 60 फीसदी जमीन आती है।

हाल के समय में भू-क्षरण को रोकने और क्षरित मिट्टी को जीवित करने की ओर ध्यान दिया गया है पर वह पर्याप्त नहीं है। इस पहलू को भी प्रस्तावित योजना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मिट्टी से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान के पास बहुत पहले से अध्ययनों का संकलन उपलब्ध है। उसका भी लाभ उठाया जाना चाहिए। मुझे भी लगता है कि नदियों के किनारे व्यापक स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि नदियों से जुड़े बड़े-बड़े संकल्प किये जाएं।

मददेनजर रखना चाहिए। उदाहरण के रूप में चक्रीय विकास प्रणाली के प्रणेता मिट्टी वैज्ञानिक पीआर मित्र का प्रयोग और उनकी उपलब्ध अनुकरणीय हैं। उन्होंने सुखना झील को पुनर्जीवित किया था। जैसा कि सरकार ने रेखांकित किया है। यदि यह योजना सफल होती है तो 13 नदियों के लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर बेसिन क्षेत्र की स्थिति गुणात्मक रूप से बदल जायेगी। जलवायु परिवर्तन की चिंता वैश्विक स्तर पर प्राथमिक है और इस समस्या की चुनौती से निपटने में भारत अधिक लाभ दिखे उसके साथ भारत का मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंध पहले से ही है। अगर घेरू अर्थव्यवस्था में बढ़त बनी रहती है भारत अमेरिका के लिए मजबूत चीन को लेकर रणनीति के बारे में सोचना होगा। अभी तक क्वाड समूह से भारत को कोई खास फायदा नहीं मिला है लेकिन भारत का रणनीतिक महत्व बढ़ सकता है। माना जा सकता है कि नयी स्थिति में अमेरिका को भारत से जुड़ने में कहीं अधिक लाभ दिखे उसके साथ भारत का मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंध पहले से ही है। अगर घेरू अर्थव्यवस्था में बढ़त बनी रहती है भारत अमेरिका के लिए मजबूत चीन के बारे में है और अब यह उस पर निर्भर करता है कि वह सावधानी से अपनी रणनीति और सक्रियता का चयन करे।

पिछले साल ग्लासगो में हुए जलवायु सम्मेलन में भारत ने बाद किया था कि 2030 तक कार्बन उत्पादन में एक अरब टन की कमी की जायेगी तथा 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जायेगा। इन्हें पूरा करने के लिए बड़ी पहलों की आवश्यकता है। नदियों के किनारे बन क्षेत्रों के विस्तार से उत्सर्जित कार्बन को सोखने में बड़ी मदद मिल सकती है। जलवायु समझौतों और अन्य अंतरराष्ट्रीय पहलों में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग बढ़ाने तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन में उत्तरोत्तर कटौती करने से जुड़े बड़े-बड़े संकल्प किये गए हैं।

पिछले साल ग्लासगो में हुए जलवायु सम्मेलन में भारत ने बाद किया था कि 2030 तक कार्बन उत्पादन में एक अरब टन की कमी की जायेगी तथा 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जायेगा। इन्हें पूरा करने के लिए बड़ी पहलों की आवश्यकता है। नदियों के किनारे बन क्षेत्रों के विस्तार की योजना ऐसा ही एक कदम है। लेकिन सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए इस पर तुरंत काम भी शुरू होना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नदियों से जुड़ी योजनाएं आम तौर पर बहुत सफल नहीं रही हैं। अच्छे अनुभवों के साथ-साथ उनकी कमियों से भी सीख लेना जरूरी है अन्यथा हम

